CPI(M)

जन जोहार झारखण्ड

अंक–04 | मासिक बुलेटिन | सितम्बर 2022

संपादकीय ....

भाजपा झारखंड में हेमंत सरकार को गिराने के लिए लिए सभी तरह के हथकंडे अपना रही है। इसके लिए सीबीआई, इडी और आयकर विभाग का उपयोग, विधायकों की खरीद फरोख्त जैसे भष्ट आचरण अपनाने में भाजपा नेतृत्व को कोई शर्म नहीं है। खनिज लीज मामले में मुख्यमंत्री पर चुनाव आयोग की क्या अनुशंसा है, इस पर पिछले 25 अगस्त से जो राजनीतिक नौटंकी चल रही है और इस अनुशंसा पर राजभवन की चुप्पी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस मामले पर अपने राजनीतिक नफा–नुकसान का आकलन कर रहा है। इस परिस्थिति में हेमंत सोरेन ने विधानसभा मे विश्वास मत हासिल कर भाजपा की साजिश को मात देने का काम किया है। लेकिन अब हेमंत सरकार को अपनी विश्वसनीयता का दायरा बढाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। हालांकि सरकार द्वारा पिछले दिनों की गयी घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राज्य में सूखे से निपटने में हो रही देरी, राशनकार्ड में छूटे हुए लोगों का नाम शामिल करने के प्रति उदासीनता, जमीन के आनलाईन रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी, कोर्ट फी और बिजली की दरों और नगर निकायों के टैक्सों में अभूतपूर्व वृद्धि, बढ़ता भष्टाचार और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति जैसे ज्वलंत मुद्दों को हल करने की दिशा में सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। इसके अलावा हेमंत सरकार को झारखंड के जनता की एकता के आधार पर एक स्थानीय नीति बनाने, यहां की भाषा व संस्कृति तथा आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने, जिसमें उनकी जमीन, संविधान की 5 वीं अनुसूची के अंतर्गत उनके लिए घोषित विशेष प्रावधानों को सख्ती से लागू किए जाने की दिशा में आगे बढना होगा। लेकिन वैसे तथाकथित प्रावधान जिसे

शेष पृष्ठ 4 पर .....

महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 20 सितंबर रांची चलो...

केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ राज्य भर में लगातार संवाद और कार्यक्रम चल रहा है जिसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव ''20 सितंबर राँची चलो'' महाजुटान है। सभी जन संगठनों और जनवादी चेतना से लैस साथी निम्नलिखित 7 सूत्री माँगों के समर्थन में 20 सितम्बर 2022 को राँची पहुँचें।

1. दाम बढ़ोत्तरी का विरोध करो –

जून 22 में तमाम वस्तुओं और सेवाओं के दामों में 7.01%, खाद्य पदार्थों के दाम में 8% और थोक दामों में भी 2021–22 में 13% की कॉरपोरेट्स द्वारा मुनाफाखोरी के लिए की गई बढ़ोत्तरी पर कठोर कार्रवाई करो। आटा, दूध, दही, पनीर इत्यादि खाद्य पदार्थों पर से 5% GST वापस लो।

पेट्रोलियम पदार्थों पर 4 तरह के सेस के माध्यम से पेट्रोल पर प्रति लीटर ₹ 27.90 और डीजल से प्रति लीटर ₹ 21.80 वसूली बंद करो। खाना पकाने के गैस सिलेंडर में मुनाफाखोरी बंद करो। अमीर कॉरपोरेट्स पर टैक्स लगाओ।

2. निजीकरण बंद करो –

न्यूनतम मजदूरी ₹ 26,000/– प्रति माह करो। सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यमों को बेचने के बजाय पुनर्जीवित करो। बेरोजगारों को रोजगार, नौकरी और बेरोजगारी भत्ता दो। सार्वजनिक संसाधनों को औने–पौने दामों पर कॉरपोरेट्स को सौंपने वाली नेशनल मोनेटाईजेशन पॉलिसी रद्द करो।

3. श्रमिक विरोधी ''4 लेबर कोड'' रद्द करो–

29 श्रम कानूनों को खारिज करके, बिना श्रमिक संगठनों से चर्चा किए, श्रमिकों की जगह मालिकों के हित में तानाशाही पूर्ण बने 4 'लेबर कोड' को रद्द करो। संविधान के अनुरूप श्रमिक संगठनों से श्रमिकों के संघर्षों से हासिल सुविधाओं को जारी रखते हुए उनकी समस्याओं, असुरक्षा और माँगों पर व्यापक स्तर पर वार्ता करके श्रमिक हित में श्रम कानून बनाओ।

3. किसानी को लाभकारी बनाओ –

23 मुख्य फसलों की स्वामिनाथन कमिटी के आधार पर MSP को कानूनी दर्जा दे कर MSP पर इनकी खरीद अविलंब सुनिश्चित करो। उत्पादक–उपभोक्ता के बीच बिना बिचौलिये के कृषि–बाजार बनाओ। 100 फीसदी खेती योग्य जमीन पर परमानेंट प्रभावी सिंचाई की व्यवस्था करो। खेती के लिए किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, अच्छे बीज, खाद, कीटनाशक उपलब्ध कराओ। किसानों को लगातार प्रशिक्षित करो। किसानों को न्यूनतम ब्याज पर कर्ज सुनिश्चित करो। बीमा का लाभ किसानो को मिले, बीमा कंपनियों को नहीं। किसानों की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेवार अधिकारियों को कड़ी सजा दो। स्कूल स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल–कॉलेज स्तर पर व्यावहारिक किसानी पाठ्यक्रम शामिल करो।

बिजली संशोधन कानून द्वारा बिजली दर बढ़ाने की साजिश बंद करो और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम दर पर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चहित करो। प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर किसानों को त्वरित और उचित मुआवजा दो।

शेष पृष्ठ 3 पर .....

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और झारखंड में स्कूली शिक्षा

शिक्षा समाज और दुनिया को बदलने (संवारने) का सर्वश्रेष्ठ संसाधन है और शिक्षा में निवेश मानव समाज के लिए सबसे ज्यादा हितकारी है। दक्षिणपंथी सरकारें, जो आदर्शवाद का चोला ओढ़े बदलाव का नारा देते हैं, दरअसल प्रतिगामी बदलावों की मंशा रखते हैं। ठोस तथ्यपरक इतिहास को नकार कर मिथकीय अंधविश्वास, पुरातनपंथ, अतीत गौरव का गुणगान करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया और उद्देश्य, दोनों में ही 'सवाल पूछना' निहित है और दक्षिणपंथियों को सवाल पूछा जाना बिलकुल पसंद नहीं। केंद्र सरकार भी इसी रास्ते पर चल रही है और उसके द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी सोच का प्रतिबिम्ब है।

मनुस्मृति की प्रचंड समर्थक केंद्र सरकार मनुवादी व्यवस्था के अनुरूप ही सवर्णों को छोड़ बाकी सबको स्तरीय–तथ्यपरक–उद्देश्यपरक शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। विदित हो कि 1901 की जनगणना में, जब रियासतों में अघोषित रूप से मनुस्मृति लागू था, जिसमें शूद्रों के लिए शिक्षा पूर्णतः वर्जित थी, साक्षर नर शूद्रों की साक्षरता दर मात्र 1% थी और महिला शूद्रों की नगण्य। स्वतंत्रता के बाद, शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 70 वर्षों के विस्तार और उपलब्धियों के विपरीत, केंद्र सरकार की शिक्षा का केंद्रीयकरण, व्यावसायिकरण और सांप्रदायिकरण करने वाली नई शिक्षा नीति 2020 बड़ी संख्या में वंचितों को स्तरीय आधुनिक शिक्षा से वंचित करना चाहती है।

संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघवाद, दोनों को दरकिनार करके, दो साल से भी पहले केंद्रीय कैबिनेट में पास हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को न आज तक संसद में पेश किया गया है और ना ही राज्यों से इस नीति पर कोई विमर्श किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रस्तावना में संविधान का जिक्र तक नहीं है। अति उत्साह में हालाँकि झारखंड सरकार ने बीआईटी मेसरा के कुलपति के नेतृत्व में एक 15 सदस्यीय कमिटी का गठन कर नई शिक्षा नीति 2020 पर सुझाव देने को कहा है।

'शिक्षा का अधिकार' के तहत 6–14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चियों–बच्चों के लिए मुफ्त और गुणवत्ता युक्त शिक्षा अनिवार्य है। इसी अधिकार के तहत निवास स्थान से एक किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर न्यूनतम 20 छात्र–छात्रा होने पर प्राथमिक स्कूल खोलने का प्रावधान है लेकिन नई शिक्षा नीति के हिसाब से तीस से कम छात्र–छात्राओं के हो जाने पर उस स्कूल का दूसरे स्कूल में विलय का प्रावधान है। पाँच किलोमीटर की परिधि में ऐसे समायोजित क्लस्टर विद्यालय बनाने का प्रावधान है। झारखंड जैसे राज्य में जंगल पार कर के बच्चों को इतनी दूर भेजना बच्चे–बच्चियों को हतोत्साहित ही करेगा। इस समायोजन के कार्य में झारखंड के 80% विद्यालय बंद करने की योजना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा 10+2 की जगह अब 5+3+3+4 की पद्धति पर 3 से 18 वर्ष की आयु तक होगी। पहले 5 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के होंगे जिसमें तीन साल प्री–स्कूल और दो साल स्कूल के होंगे। इसकी जिम्मेवारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को बिना किसी निर्धारित

शेष पृष्ठ 4 पर .....

हालात !

एडवा का दो दिवसीय झारखंड राज्य सम्मेलन

चौतरफा संकट का सामना कर रही महिलाएँ, कोरोना काल के बाद एक ओर जहां रोजगार के संकट से जूझ रही हैं, वहीं दुसरी ओर बढ़ती मंहगाई ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है। हाल के दिनों में झारखंड जैसे राज्य में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ने संवेदनशील नागरिकों को स्तब्ध कर दिया है। इस एक सप्ताह में ही दुमका की नवयुवती अंकिता को पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं चतरा के हंटरगंज में एक युवती पर तेजाब फेंक कर उसे बुरी तरह घायल किए जाने का जघन्य अपराध किया गया। अब वह युवती अस्पताल में जीवन के लिए मौत से संघर्ष कर रही है। बलात्कार की बढ़ती घटनाएं जिसमें छोटी–छोटी बच्चियों को भी बहशी दरिंदों द्वारा शिकार बनाए जाने की घटनाओं ने महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है– झारखंड में ही 'बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ' का नारा देने वाली भाजपा नेत्री द्वारा अपने ही नाबालिग घरेलू कामगार आदिवासी लड़की सुनीता को दरिंदगी की पराकाष्ठा दिखाते हुए

शारीरिक रूप से यातना दिए जाने के मामले ने आम लोगों को आक्रोशित कर दिया है।

यह बात 31 अगस्त को एडवा के झारखंड राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि सत्र का उद्घाटन करते हुए एडवा की अखिल भारतीय अध्यक्ष मालिनी भट्टाचार्य ने कही। उन्होंने कहा कि महिलाऐं संगठित होकर ही इस प्रकार के हमलों का मुकाबला कर सकती हैं।

सम्मेलन की शुरुआत 30 अगस्त को एडवा का झंडा फहराये जाने और एक प्रभावी रैली से की गई जिसमें विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों के अलावा संगठन की स्थानीय महिलाओं की भागीदारी हुई।

सम्मेलन के खुले सत्र का उद्घाटन करते हुए जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय महासचिव मरियम धावले ने कहा कि एडवा खाद्य सुरक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार और उनकी सुरक्षा की गारंटी जैसे मुद्दों पर पुरे देश में लगातार आंदोलन चला रही है। इसके

..... शेष पेज 3 पर

डायन बताकर अंधविश्वास में हत्या

दिनांक 7 सितंबर 2022 को माकपा, किसान सभा एवं जनवादी महिला समिति की 5 सदस्यीय जांच टीम राणाडीह गांव पहुंच कर डायन हत्या में मृतक रातुमनी देवी, राईलू देवी एवं एतवारी देवी के परिजनों एवं ग्रामीणों से मिले। सांप काटने से राजकिशोर मुंडा की मौत हुई लेकिन अंधविश्वास में ओझा सुकरा मुंडा के बहकावे में आकर कारण तीन महिलाओं को डायन बताकर कर नृशंसता से पीट, पीट कर, पत्थर से कूच कर उनकी हत्या कर दी गई।

माकपा जांच टीम ने राणाडीह डायन हत्याकांड की न्यायिक जांच कराने, मृतक के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा एवं सुरक्षा देने, ओझा, गुणी पर प्रतिबंध लगाने तथा आदिवासी, दलित, पिछड़े गांव में सरकार द्वारा निरंतर डायन प्रथा, अंधविश्वास विरोधी अभियान चलाने की मांग की। साथ ही आदिवासी संगठनों, सामाजिक संगठनों से भी गांव सभाओं के जरिए डायन प्रथा एवं अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाने की अपील की।

माकपा, जनवादी महिला समिति और किसान सभा डायन हत्या एवं अंधविश्वास के खिलाफ हर गांवों में अभियान तेज करेगी। □

झारखण्ड शिक्षा मंच का कन्वेंशन

शिक्षक दिवस के अवसर पर 'शिक्षा बचाओ, देश बचाओ' को लेकर 'झारखंड शिक्षा मंच' का एक दिवसीय कन्वेंशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड, साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड व झारखंड साइंस फोरम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हुआ।

कन्वेंशन कार्यक्रम में शिक्षा नीति 2020 के परिपेक्ष्य में झारखंड की शिक्षा की स्थिति, ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा स्कूली शिक्षा का सर्वेक्षण और सामुदायिक शिक्षण केंद्र के संदर्भ, झारखंड में उच्च शिक्षा की स्थिति शिक्षा नीति 2020, स्कूली पूर्व शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति, चिकित्सा शिक्षा, वयस्क शिक्षा की चुनौतियों आदि विषयों को लेकर चर्चा की गई।

भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. काशी नाथ चटर्जी द्वारा कन्वेंशन के उद्देश्य और आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया।

मुख्य वक्ता, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. ज्यां द्रेज ने कहा कि संयुक्त बिहार के समय से बीजीवीएस के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्यरत रहे और किए मीड–डे मील तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाने में सक्रिय रहे। कोविड से जब शिक्षा प्रभावित हुआ, खास कर सरकारी विद्यालय के शिक्षा से बच्चे दूर हुए उस समय भी बीजीवीए के साथ मिलकर शिक्षा की स्थिति पर सर्वे का कार्य किया। आज की शिक्षा नीति की बात करें तो गरीब बच्चों के लिए जहां घर तक विद्यालय की व्यवस्था थी, अब क्लस्टर स्तर पर विद्यालय मर्जकी बात की जा रही है जो पांच किलो मीटर के दायरे में होगा और वांचितों को शिक्षा विमुख करेगा।

कन्वेंशन को प्रो. ए. ए. खान, ए. आई. खान, शर्मिष्ठा सेनगुप्ता, शिवशंकर, समीर दस, मो सिद्दीकी ने भी संबोधित किया। □

रेलवे का निजीकरण का साजिश

भारत सरकार द्वारा बुनियादी संरचना विकास के लिए ₹111 लाख करोड़ खर्च वर्ष 2019–25 की अवधि के लिए तय किया गया था, जिसमें से भारतीय रेल के लिए ₹13.69 लाख करोड निवेश करने का लक्ष्य है। चूंकि निजी कंपनियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना नही चाहती हैं तो भारत सरकार ने ₹13.69 लाख करोड का 87% हिस्सा बजट सपोर्ट से खर्च करने का निर्णय लिया है जिसके अनुसार वर्ष 22–23 के बीच ₹10.50 लाख करोड रूपया बजट राशि रखना था, लेकिन मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपए ही रखा गया। फलस्वरूप योजना विफल हो गई। अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से रेलवे मे निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया है।

रेलवे–निजीकरण के प्रस्ताव अनुसार वर्ष 2023 मार्च के अंदर 12 क्लस्टर से चलने वाली 150 यात्रीगाड़ी का परिचालन निजी हाथों में देने का फैसला है। निजी कंपनी को ये आश्वासन दिया गया था कि निजी गाड़ी चलने के 60 मिनट पूर्व या 60 मिनट बाद ही रेलवे अपनी गाड़ी चलाएगी। इसके लिए निजी कम्पनियों को 35 वर्ष का लाईसेंस दिया जायगा। निजी कम्पनियां टिकट का दर खुद तय करेंगी और कोई भी श्रेणी का गाड़ी चला सकेंगी। निजी कम्पनियां तृतीय श्रेणी का वातानुकूलित गाड़ी चलाने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि यह अधिक लाभप्रद है। वे द्वितीय श्रेणी अनारक्षित तथा शयनयान चलाने में उत्सुक नही हैं। निजी कंपनियां रेलवे द्वारा निर्मित टिकट बुकिंग सुविधा, प्लेटफार्म, रेलमार्ग, सिग्नल एवं गार्ड–ड्राइवर आदि का प्रयोग करेंगी जिसके एवज में रेलवे को हौलेज चार्ज देगी। सिर्फ IRCTC तथा मेगा ईंजिनियरिंग कंपनी दिल्ली तथा मुंबई क्लस्टर के लिए आगे आई और वो भी ₹100 आमदानी में सिर्फ ₹54 हौलेज चार्ज देने की शर्त पर। कोई रेवेन्यू शेयरिंग नहीं। गाड़ी परिचालन का लाईसेंस भी उन्हें मुफ्त में चाहिए। संसद में सवाल के जवाब में बताया गया कि वह टेंडर कैंसल कर दी गई है।

मोदी सरकार 2014 से ही स्टेशनों का निजीकरण करना चाह रही थी और 400 स्टेशन की सूची भी तैयार की गई थी। बाद मे सूची बदलकर 50 और फिर 28 स्टेशनों की की गई। पर अभी तक सिर्फ एक ही स्टेशन का निजीकरण हुआ है, हबीबपुर जंक्शन। रेलवे के निजीकरण से भाड़े में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी, छँटनी होगी और यात्री सुरक्षा भी प्रभावित होगी। माकपा मोदी सरकार के रेलवे को ले कर जनविरोधी नीति का पुरजोर विरोध करती है। □

..... तापस चट्टराज।

कविता

अभी जयकारे हैं तेरे,
तुम्हें खुदा बताया जाएगा,
जो मैं आईना दिखा दूँ,
मुझे सूली चढ़ाया जाएगा।

कुछ देर की खामोशी है,
सुनो, फिर शोर आएगा,
अभी सिर्फ वक्त है तेरा ,
अब हमारा दौर आएगा।

दलितों को उजाड़नेवालों को सजा दो

पलामू जिला अंतर्गत पांडू प्रखंड में दबंग सामंतों द्वारा पीढ़ियों से बसे दलितों को जबरन बेदखल किए जाने की घटना चिंताजनक है।

माकपा राज्य सरकार से अविलंब दलितों को उजाड़ें जाने की कार्रवाई पर रोक लगाने और किसी सचिव स्तर के उच्च अधिकारी के नेतृत्व में पलामू एक टीम भेजकर इन घटनाओं की जांच कराए जाने के साथ ही उजाड़े गये दलित परिवारों को उक्त जमीन पर फिर से बसाने और उन्हें अविलंब बासगीत का पर्चा दिए जाने की मांग करता है। माकपा इन घटनाओं पर पलामू जिला प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना भूमिका की भी जांच कराए जाने की मांग करता है। □

महंगाई और बेरोजगारी ...

..... शेष पेज 1 का

4. भूमिहीन ग्रामीण –

भूमि सुधार के माध्यम से सभी भूमिहीन ग्रामीणों को जमीन का पट्टा दो। तब तक भूमिहीनों को मनरेगा के तहत साल में न्यूनतम 200 दिन ₹ 600/– प्रतिदिन की दर से काम दो।

5. सबके लिए वैज्ञानिक शिक्षा और स्वास्थ्य –

शिक्षा के अधिकार के तहत सबके लिए निःशुल्क, उत्कृष्ट और सहज विज्ञान आधारित शिक्षा अनिवार्य घोषित करो। निजी शिक्षण संस्थान के मकड़जाल को बंद करो। निजीकरण, व्यवसायिकरण, केन्द्रीयकरण और साम्प्रदायिकरण को थोपने वाली नई शिक्षा नीति रद्द करो। शिक्षा पर कुल बजट का 6 प्रतिशत खर्च करो।

सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार लागू करो। सबके लिए निःशुल्क, उत्कृष्ट और त्वरित स्वास्थ्य उपलब्ध कराओ। निजी अस्पतालों के मकड़जाल को बंद करो। स्वास्थ्य का बजट आवंटन बढ़ाओ।

6. हर हाथ को काम –

सबके लिए काम के अधिकार को तुरंत लागू करो। ₹ 26,000/– प्रतिमाह की तनख्वाह पर सबके लिए परमानेंट नौकरी/रोजगार सुनिश्चित करो। तब तक केरल सरकार की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी नियम लागू करो।

7. जनतांत्रिक अधिकारों पर हमला बंद करो –

सभी राजनैतिक कैदियों और पत्रकारों को बिना शर्त तुरंत रिहा करो। शिकायतकर्ता को ही अपराधी घोषित करना बंद करो। अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों व महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करो। विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन हड़पना बंद करो। दलितों पर अत्याचार करने वालों को कठोर सजा दो। राजद्रोह कानून रद्द करो। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ED, CBI, NIA जैसे केन्द्रीय संस्थानों का दुरूपयोग बंद करो। संघवाद एवं संवैधानिक संरचना पर हमला बंद करो। UAPA जैसे कानूनों को तुरंत रद्द करो। सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर न्याय व्यवस्था जनपक्षीय बनाओ। संसद की गरिमा बहाल करो।

एडवा ...

..... शेष पेज 2 का

अलावा महिलाओं को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किए जाने की सांप्रदायिक ताकतों की साजिशों का भी विरोध कर रही है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का विधयक राज्य सभा से पारित हो जाने के बावजूद केंद्र में सत्तारूढ़ सभी सरकारों ने इसे लोकसभा से पारित कराए जाने में अड़ंगा ही लगाया है। इसलिए महिलाओं को अपने अधिकारों को लेने के लिए तीखा संघर्ष छेड़ना होगा।

एडवा की राज्य सचिव प्रो. शिवानी पाल ने सम्मेलन में राजनीतिक–सांगठनिक रिपोर्ट पेश किया जिसमें पिछले तीन वर्ष की गतिविधियों को दर्शाया गया था। सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा का अभाव, राज्य की महिला आबादी का परिवार के साथ या अकेले काम की तलाश में राज्य से बाहर पलायन जिनमें अधिकांश आदिवासी महिलाएं हैं। आने वाले दिनों में विस्थापन और पलायन की समस्या पर एडवा एक संगठित और लगातार चलने वाले आंदोलन की कार्ययोजना बनाएगी।

सम्मेलन द्वारा 11 प्रस्ताव पारित किए गए। जिसमें, महंगाई को नियंत्रित किए जाने के लिए अनाज समेत खाने–पीने (शराब छोड़कर) की सभी वस्तुओं पर लागू किए गए जीएसटी को वापस लेने, पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैस की कीमत कम करने, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने, राशन कार्ड में छुटे हुए लोगों का नाम शामिल करने, निर्वाचित पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने, जमीन का ऑनलाइन रिकार्ड ठीक करने, महिला आरक्षण बिल अविलंब पारित करने, गुजरात में विल्किस बानो हत्याकांड के अभियुक्तों को पुनः जेल भेजने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस–प्रशासन को संवेदनशील बनाने, एकल महिलाओं की समस्याओं का निराकरण के लिए जिला स्तर पर एक सेल बनाने और जेंडर समानता के लिए स्कूलों से ही अभियान संगठित किए जाने का मुद्दा शामिल था।

सम्मेलन में एडवा के डेलिगेट्स पूरे प्रदेश में फैले 74 हजार सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

सम्मेलन के अंत में प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से एडवा की 26 सदस्यीय राज्य कमिटी का चुनाव किया जिसमें प्रोफेसर शिवानी पाल अध्यक्ष, वीणा लिंडा राज्य सचिव और माया लायक कोषाध्यक्ष चुनी गईं। इसके अलावा रंगोवती देवी, उपासनी महताईन और जया मजुमदार उपाध्यक्ष, रेणू दास, पानमुनी किस्कू और पुतूल महतो संयुक्त सचिव चुनी गई। □ – एडवा

मजदूरों का कन्वेंशन सम्पन्न

सेल द्वारा परिचालित कोलियरी डिविजन के अन्तर्गत जितपुर, चासनाला, रामनगर और टांसरा कोलियरी के संयुक्त मोर्चा के साथ आम मजदूरों का कन्वेंशन हुआ जिसमें उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए और मजदूरों की मांग को लेकर सेल प्रबंधन की नाकारात्मक और मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ आन्दोलन की तैयारी और कार्यक्रम लिए गए । □

माकपा और भाकपा की राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा

2 सितम्बर को हजारीबाग परिसदन में माकपा और भाकपा के राज्य नेतृत्व की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ निर्वाचन आयोग की अज्ञात अनुशंसा से राज्य में पैदा हुए राजनीतिक संकट पर चर्चा की गई माकपा और भाकपा जैसे वामदलों की स्पष्ट समझ है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पुरे देश में विरोध पक्ष की किसी भी चुनी हुई सरकार को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने देने का बहुत ही घटिया और लोकतंत्र विरोधी खेल कर रही है।

महाराष्ट्र में सरकारी एजेंसी और राजभवन का इस्तेमाल कर उद्धव ठाकरे सरकार को अनैतिक तरीके से गिराने से उत्साहित हो कर हेमंत सोरेन की सरकार गिराने में लग गई है। हथकंडे वैसे ही हैं। झारखंड की जनता भाजपा के इस लोकतंत्र विरोधी षडयंत्र से पुरी तरह वाकिफ है और समय आने पर इसका माकूल जवाब देगी। भाकपा और माकपा ने झारखंड की जनता का आह्वान किया है कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जारी संघर्ष को और तेज करें।

इस बैठक में भाकपा के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, माकपा के पूर्व केंद्रीय कमिटी सदस्य ज्ञान शंकर मजुमदार और माकपा के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव एवं माकपा नेता गणेश कुमार सीटू उपस्थित थे। □

सम्पादकीय पेज 1 का शेष .....

कानूनी रूप से निरस्त कर दिया गया है उसे उठाकर फिर से झारखंड की जनता को विभाजित करने की कोशिश राज्य के व्यापक हितों को कमजोर करेगा।

सीपीएम राज्य के उपरोक्त जन मुद्दों, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पूरे सितंबर माह मे जनता के बीच सघन अभियान चला रही है यह अभियान 20 सितंबर को अपने उत्कर्ष पर पहुंचेगा जब पूरे झारखंड से हजारों लोग राजधानी रांची में महाजूटान कर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा आमलोगों के जीवन जीविका पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ आने वाले दिनों में बड़े जनसंघर्ष आयोजित किए जाने का संकल्प लेंगें. □

आंगनबाड़ी सेविकाओं का बढ़ा मानदेय

झारखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में झारखंड सरकार द्वारा बढ़ोतरी किए जाने का सीटू स्वागत करता है। यह बढ़ोतरी आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा किए गए संयुक्त संघर्ष का परिणाम है। कोरोना के समय इन आइसीडीएस कार्यकर्ताओं ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का पालन किया था।

सीटू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी बधाई देता है कि उन्होंने किए गए वायदे को पूरा किया है। सीटू, मुख्यमंत्री से अपील करता है कि झारखंड जैसे राज्य में जहां कुपोषण जैसी समस्या से ग्रामीण और शहरी गरीबों के बच्चे प्रभावित हैं, वहाँ राज्य के 8 सबसे ज्यादा कुपोषित जिले में कार्यरत 10 हजार पोषण सखी को पुनः नियुक्त किया जाय। □

साम्प्रदायिक दंगों में झारखण्ड अव्वल

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के आंकड़ों से यह तथ्य सामने आया है कि वर्ष 2021 मे पूरे देश में कुल 378 सांप्रदायिक देंगे हुए थे, इनमें से अकेले झारखंड में 100 दंगे हुए।

यह तथ्य झारखंड के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों, प्रगतिशील सामाजिक संगठनों और श्रमिक संगठनों के लिए चिंता का विषय है। सभी तरह के सांप्रदायिक संगठन आम जनता के बीच नफरत की मुहिम फैलाकर सद्भाव और एकता के खिलाफ संगठित दुष्प्रचार चला कर झारखंड के शांतिप्रिय माहौल को विषाक्त कर रहे हैं। माकपा इन तत्वों के खिलाफ अन्य वामपंथी तथा लोकतांत्रिक संगठनों से लगातार जारी संयुक्त वैचारिक अभियान को और तेज करने का आह्वान करती है। □

राष्ट्रीय शिक्षा .....

..... शेष पृष्ठ 1 का

पाठ्यक्रम के दी जाएगी। अगले तीन साल कक्षा 3, 4, 5 फाउंडेशन कोर्स का होगा, जिसमें घर की बोलचाल, स्थानीय, मातृ भाषा में शिक्षण का कार्य होगा। अगले तीन साल 6, 7, 8 में शिक्षा को बहुभाषी बनाने के साथ एक क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी मिलेगा। अंतिम चार वर्ष 9, 10, 11, 12 वाले भाग में विदेशी भाषा सीखने के साथ अन्य प्रावधान होंगे। 'दीक्षा' (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) द्वारा शिक्षा को व्यापक बनाने की बात कही गई है। बिना किसी तैयारी के इस ढाँचागत बदलाव के साथ–साथ प्रबंधन, मूल्यांकन, नियमन, ग्रेडेशन पद्धति में भी परिवर्तन करने की तैयारी है।

कुछ और चौंकाने वाले आँकड़े हैं। 5 सितंबर 22, शिक्षक दिवस को प्रधानमंत्री ने फरवरी 2021 में देश की वित्त मंत्री के बजट भाषण में उल्लेखित 15,000 पीएमश्री विद्यालयों की संख्या घटा कर 14,500 करने की फिर से घोषणा की है। डेढ़ साल बीत जाने के बाद स्वरूप तक तय नहीं हुआ है, सिर्फ पुनर्घोषणा ही हुई है। गिनती के केंद्रीय–नवोदय–कस्तूरबा–सैनिक स्कूलों और कुकरमुत्ते से फैलते निजी स्कूलों को छोड़ दें तो भी 85–90% स्कूल सरकारी स्कूल ही हैं, जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। आधारभूत संरचना की कमी, 80% से ज्यादा शिक्षकों की कमी, बाकी 20% में भी पाराशिक्षक और अनुबंध पर शिक्षक, 40% स्कूलों में शौचालय का ना होना, 80% स्कूलों में शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता, राज्य में शिक्षा की स्थिति को भयावह बनाती है। झारखंड में 28,010 प्राइमरी, 15,951 अपर प्राइमरी, 3,372 सेकेंडरी और 1,229 सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हैं जिसमें 30% एकल शिक्षक विद्यालय है। विद्यालयों की संख्या मात्र पर सरसरी निगाह डालने से ही सरकारों की शिक्षा–विरोधी मंशा साफ झलकती है। शिक्षा सत्ता की प्राथमिकताओं में नहीं है, जो शिक्षा बजट के आवंटन में भी स्पष्ट दिखता है। आवंटित बजट में भी मुख्य हिस्सा ठेकेदारों और प्रचार पर ही खर्च होता है। स्कूलों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी जैसे प्रमुख मुद्दे पर भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कोई जिक्र नहीं है।

इसके विपरीत शिक्षा हम आमजन के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय है। आप–हम सबको मिलकर इसे अपनी राजनीति के केंद्र में रखना है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण, तथ्यपरक और मानवीय मूल्यों वाली शिक्षा हमारा अधिकार है। शिक्षा की बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करने के लिए देश के कुल बजट का 10% अगले पाँच वर्षों के लिए और उसके बाद 6% आवंटित करना, सभी विद्यालयों में हर 30 छात्र–छात्रा पर एक शिक्षक के आधार पर गुणी स्थायी शिक्षकों की भर्ती करना, सभी बच्चे–बच्चियों के लिए सीनियर सेकेंडरी तक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य करना, स्कूली प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी आदि माँगों को लेकर हमें एकजुट होकर शिक्षा को भी हमारे आंदोलनों का प्रमुख हिस्सा बनाना होगा।□

कोष संग्रह कार्यक्रम तस्वीरों में ...

बाराहाट

गोमिया

बहरागोड़ा

जमशेदपुर

सिंदरी

बोड़ाम

कोडरमा

दुमका

धनबाद

अगलोई

लोदना बाजार

अड़की, खूँटी

पार्टी कोष में सहयोग की अपील

संघर्ष कोष के लिये स्वेच्छा से निम्नलिखित बैंक खाते में अपना

Communist Party of India Marxist
Bank : Bank of Baroda
Main Branch, Ranchi
A/c No. : 00170200000219
IFSC Code : BARB0RANCHI

सीपीआई (एम) राज्य कमिटी, झारखण्ड की ओर से राज्य सचिव प्रकाश विप्लव द्वारा संपादित एवं प्रेषित। संकलन एवं संयोजन सुधांशु शेखर, अमल पाण्डेय व बिपिन कु0 सिन्हा।
अधिक जानकारी एवं सुझाव के लिये सम्पर्क करें– माकपा पार्टी कार्यालय, विश्वकर्मा मंदिर लेन, मेन रोड, रांची–834001, ई–मेल : janjohar.jharkhand@gmail.com